

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 178/2024

(अपील संख्या – 4653/2019)

रामकल्याण चन्देल

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- डॉ. दीपक माहेश्वरी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
- डॉ. आशा वर्मा, अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2024

आदेश की दिनांक : 06.11.2024

उपस्थित :-

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

- प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 4653/2019 में दिनांक 15.04.2024 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 15.04.2024 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 1987 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्यॉय के पद पर की गई थी और उसे दिनांक 06.02.1987 के द्वारा एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर से जनाना अस्पताल, जयपुर पदस्थापित किया गया। तब से अपीलार्थी निरंतर कार्यरत है। आदेश दिनांक 09.03.1993 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.09.1987 से अपीलार्थी

की सेवायें निरंतर मानते हुये वार्ड ब्यॉय के उपलब्ध रिक्त पद पर वेतन श्रृंखला 750-940 में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से नियुक्त दिनांक में भी वरिष्ठ है तथा समान पद पर कार्यरत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 03.09.1987 से महिला चिकित्सालय में तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 25.08.2012 से महिला चिकित्सालय में कार्यरत था। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 25.02.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के द्वारा कार्मिकों को स्थायी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 2 पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 22 पर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से वरिष्ठ है, फिर भी आदेश दिनांक 24.06.2019 के द्वारा जो वरिष्ठता सूची जारी की गई, उसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम अंकित किया गया है, परंतु अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की, परंतु विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई और अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। इस प्रकार हमारे मत में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम से वरिष्ठ कार्मिक है, परंतु वरिष्ठ होने के बावजूद उसके नाम पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाना विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम से वरिष्ठ है। अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद उसे पदोन्नति से वंचित रखा जाना नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिव्यू डीपीसी की जाकर जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार उक्त पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि दिये जावें।”

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.04.2024 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.04.2024 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
3. अप्रार्थी-प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई

अवमानना कारित नहीं की गयी है। माननीय अधिकरण के आदेशों की पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी-अपीलार्थी की अवमानना याचिका को निरस्त फरमावे।

4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व अप्रार्थी-प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तथ्यों की पुनरावृत्ति की।
5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2024 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 1987 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्यॉय के पद पर की गई थी और उसे दिनांक 06.02.1987 के द्वारा एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर से जनाना अस्पताल, जयपुर पदस्थापित किया गया। तब से अपीलार्थी निरंतर कार्यरत है। आदेश दिनांक 09.03.1993 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.09.1987 से अपीलार्थी की सेवायें निरंतर मानते हुये वार्ड ब्यॉय के उपलब्ध रिक्त पद पर वेतन श्रृंखला 750-940 में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से नियुक्त दिनांक में भी वरिष्ठ है तथा समान पद पर कार्यरत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 03.09.1987 से महिला चिकित्सालय में तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 25.08.2012 से महिला चिकित्सालय में कार्यरत था। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 25.02.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के द्वारा कार्मिकों को स्थायी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 2 पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 22 पर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 से वरिष्ठ है, फिर भी आदेश दिनांक 24.06.2019 के द्वारा जो वरिष्ठता सूची जारी की गई, उसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम अंकित किया गया है, परंतु अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने वरिष्ठता सूची के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की, परंतु विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई और अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। इस प्रकार हमारे मत में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम से वरिष्ठ कार्मिक है, परंतु वरिष्ठ होने के बावजूद उसके नाम पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाना विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी श्री ग्यारसी लाल एवं श्री हरि ओम से वरिष्ठ है। अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद उसे पदोन्नति से वंचित रखा जाना नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिब्यू डीपीसी की जाकर जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार उक्त पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि दिये जावें।”

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted

by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 15.04.2024 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी—अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)